>

Title: Need to abolish the custom duty on ship-breaking industry.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से बार–बार पत्राचार करके अलग शिप ब्रेकिंग हेतु कस्टम डयूटी में 5 प्रतिशत से शून्य करने की विनती की है जिसे केन्द्र सरकार ने मना कर दिया है। तदोपरान्त राज्य सरकार ने उपरोक्त मामले में स्पष्टीकरण सहित दुबारा विचार करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूँ कि उपरोक्त मामले में पुनः अवलोकन करें एवं कस्टम डयूटी को कम करे।